भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1982

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना

1982. श्री मनसुख एल. मांडवियाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को आवश्यक आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से परामर्श करते हुए आपके मंत्रालय द्वारा आज तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों में साइबर अपराधों से जुड़े राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): (i) सरकार ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केरल, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में साइबर विधि विज्ञान प्रशिक्षण एवं जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

(ii) गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध एवं विधि विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस) ने दांडिक न्याय प्रणाली पदाधिकारियों के लिए 'डिजिटल साक्ष्य एवं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पाठ्यक्रम' तैयार किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान एनआईसीएफएस ने 155 दांडिक न्याय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

(iii) एनआईसीएफएस ने 'ए फॉरेंसिक गाइड फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्सः स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रॉसीजर्स' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में देश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, जांच एजेंसियों तथा केन्द्रीय/राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के

संवितरण के लिए डिजिटल साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण तथा पैकेजिंग और उसके अग्रेषण के संबंध में पुलिस कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए 'डिजिटल साक्ष्य' पर एक अध्याय संख्या 20 है।

(ख): वर्ष 2012-14 की अवधि के दौरान सूचित अद्यतन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामले अनुलग्नक-I के रुप में संलग्न है।

अनुलग्नक।

दिनांक 11.5.2016 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1982 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

2012-14 के दौरान कुल साइबर अपराध के तहत दर्ज राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामले				
क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012	2013	2014*
1	आंध्र प्रदेश	454	651	282
2	अरुणाचल प्रदेश	12	10	18
3	असम	28	154	379
4	बिहार	30	139	114
5	छत्तीसगढ़	59	101	123
6	गोवा	32	58	62
7	गुजरात	78	77	227
8	हरियाणा	182	323	151
9	हिमाचल प्रदेश	20	28	38
10	जम्मू और कश्मीर	35	46	37
11	झारखंड	35	26	93
12	कर्नाटक	437	533	1020
13	केरल	312	383	450
14	मध्य प्रदेश	197	342	289
15	महाराष्ट्र	561	907	1879
16	मणिपुर	0	1	13
17	मेघालय	6	17	60
18	मिजोरम	0	0	22
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	27	104	124
21	पंजाब	78	156	226
22	राजस्थान	154	297	697
23	सिक्किम	0	0	4
24	तमिलनाडु	41	90	172
25	तेलंगाना	-	-	703
26	त्रिपुरा	14	14	5
27	उत्तर प्रदेश	249	682	1737
28	उत्तराखंड	4	27	42
29	पश्चिम बंगाल	309	342	355
30	अं.और नि. द्वीपसमूह	2	18	13
31	चंडीगढ़	33	11	55
32	दादर और नगर हवेली	0	0	3
33	दमण और दीव	0	1	1
34	दिल्ली	84	150	226
35	लक्षद्वीप	0	0	1
36	पुदुचेरी	4	5	1
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	123	185	300
	कुल (अखिल भारत)	3477	5693	9622
स्रोत: एनसीआरबी				
नोट: '*' में आईटी एक्ट एवं आईपीसी अपराधों के साथ विशेष एवं स्थानीय कानून वाले अपराध भी शामिल है				